RNI No#MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 7 से 06 फरवरी 2026 | भोपाल , मध्यप्रदेश से प्रकाशित | वर्ष- 13 | अंक-78 | पृष्ठ- 8 | मूल्य- रु. 5 /-

बैंकिंग सेक्टर में FDI प्रवाह में बड़ी गिरावट: FY23 के 898 मिलियन डॉलर से FY25 में सिर्फ 115 मिलियन डॉलर

वैश्विक अनिश्चितता और नियामक सख्ती से निवेश प्रभावित, प्राइवेट बैंकों में भी रुचि घटी; RBI और सरकार से नीतिगत सुधार की मांग

नई दिल्ली: भारत के बैंकिंग सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) में पिछले दो वर्षों में तेज गिरावट आई है। RBI और वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, FY23 में बैंकिंग सेक्टर में FDI 898 मिलियन डॉलर रहा था, जो FY25 में घटकर मात्र 115 मिलियन डॉलर रह गया। यह 87% से अधिक की कमी दर्शाता है, जो वैश्विक निवेशकों के बीच भारतीय बैंकिंग पर भरोसे में आई कमी को उजागर करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस गिरावट के कई कारण हैं। वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी, अमेरिका-चीन व्यापार तनाव और भारत में साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल लेंडिंग पर सख्त नियमों ने विदेशी निवेशकों को सतर्क किया है। प्राइवेट बैंकों में भी FDI रुचि घटी है, जहां पहले HDFC, ICICI और Axis बैंक बड़े निवेश आकर्षित करते थे। FY24 में भी FDI 300 मिलियन डॉलर से नीचे रहा था।

बैंकिंग सेक्टर में FDI की सीमा 74% है, लेकिन कई विदेशी बैंक पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई बनाने में रुचि नहीं दिखा रहे। RBI की साइबर सुरक्षा और NPA नियंत्रण पर सख्ती ने भी निवेशकों को प्रभावित किया है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह अस्थायी हो सकता है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और क्रेडिट ग्रोथ 12% से अधिक बनी हुई है।

FDI की कमी से बैंकिंग सेक्टर की पूंजी बढ़ाने की गति धीमी हुई है। विशेषज्ञों ने सरकार से FDI सीमा बढ़ाने और नियामक प्रक्रिया को आसान बनाने की अपील की है। FY26 में यदि सुधार हुए तो FDI फिर से बढ़ सकता है। यह गिरावट भारत की वित्तीय क्षेत्र में विदेशी पूंजी के प्रति बदलते नजरिए को दर्शाती है।

भारत में विस्तार से गोल्डमैन सैक्स को मिला नया विकास इंजन

भारतीय बाजार से रिकॉर्ड राजस्व, सलाहकार और ट्रेडिंग में मजबूत स्थिति; 2025 में भारत से 1.5 अरब डॉलर कमाई, एशिया में सबसे तेज विकास

भोपाल: गोल्डमैन सैक्स ने भारत में अपनी उपस्थिति को मजबूत करके वॉल स्ट्रीट के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में अलग मुकाम हासिल किया है। कंपनी ने 2025 में भारत से रिकॉर्ड राजस्व कमाया, जो इसकी भारतीय रणनीति की सफलता को दर्शाता है। गोल्डमैन सैक्स के एशिया-प्रशांत प्रमुख ने हाल ही में कहा कि भारत अब कंपनी के लिए सबसे तेज बढ़ता बाजार है, जहां राजस्व में 30% से अधिक की सालाना वृद्धि हुई है।

भारत में गोल्डमैन सैक्स की कमाई 2025 में 1.5 अरब डॉलर के करीब पहुंच गई, जो मुख्य रूप से इक्विटी कैपिटल मार्केट्स, M&A सलाहकार सेवाओं और ट्रेडिंग से आई। कंपनी ने भारतीय कंपनियों के लिए कई बड़े IPO और QIP में लीड भूमिका निभाई, जिनमें से कई 2025 में सफल रहे। साथ ही, भारतीय कॉर्पोरेट्स के विदेशी अधिग्रहण और क्रॉस-बॉर्डर डील्स में गोल्डमैन की सलाहकार भूमिका बढ़ी है।

भारत में कंपनी की टीम अब 1,500 से अधिक लोगों की हो चुकी है, जिसमें मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली में मजबूत उपस्थिति है। गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स में भी निवेश बढ़ाया है। कंपनी का कहना है कि भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, डिजिटल अर्थव्यवस्था और युवा जनसंख्या इसे वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक बनाती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि गोल्डमैन सैक्स की सफलता अन्य वॉल स्ट्रीट दिग्गजों के लिए सबक है। भारत में बढ़ती पूंजी बाजार गतिविधि और विदेशी निवेशकों की रुचि से कंपनी कोफायदा हुआ है। 2026 में भी भारत से दोहरे अंकों में वृद्धि की उम्मीद है। यह उपलब्धि भारत को वैश्विक वित्तीय केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

नीति आयोग ने CAFE नियमों के तहत छोटी कारों के लिए प्रोत्साहन की मांग की

छोटे इंजन वाली कारों को अधिक क्रेडिट, ईंधन दक्षता बढ़ाने का लक्ष्य; ऑटो इंडस्ट्री को राहत, EV ट्रांजिशन में भी मदद

नई दिल्ली: नीति आयोग ने CAFE (Corporate Average Fuel Efficiency) नियमों में संशोधन की सिफारिश की है, जिसमें छोटी कारों (1.2 लीटर से कम इंजन) के लिए अधिक प्रोत्साहन और क्रेडिट दिए जाएं। आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है कि छोटी कारों को बेहतर ईंधन दक्षता क्रेडिट मिले, ताकि ऑटोमोबाइल कंपनियां इन पर ज्यादा फोकस करें। यह सिफारिश ऐसे समय आई है जब छोटी कारों की बिक्री में गिरावट आई है और SUV की मांग बढ़ रही है।

CAFE नियमों के तहत कंपनियों को औसतन 18-20% ईंधन दक्षता हासिल करनी होती है। नीति आयोग का कहना है कि छोटी कारें ईंधन की बचत करती हैं, लेकिन SUV की बढ़ती बिक्री से कंपनियां बड़े इंजन पर फोकस कर रही हैं। छोटी कारों को अधिक क्रेडिट मिलने से कंपनियां इन्हें सस्ता और आकर्षक बना सकेंगी।

ऑटो इंडस्ट्री ने इस सिफारिश का स्वागत किया है। SIAM के एक अधिकारी ने कहा, "यह कदम छोटी कारों को फिर से प्रतिस्पर्धी बनाएगा और मध्यम वर्ग के लिए सस्ती कारें उपलब्ध होंगी।" नीति आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि हाइब्रिड और छोटे इलेक्ट्रिक वाहनों को भी CAFE में अतिरिक्त लाभ मिले, ताकि EV ट्रांजिशन तेज हो।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव 2030 तक भारत के 30% EV लक्ष्य को सपोर्ट करेगा। छोटी कारों की बिक्री बढ़ने से ईंधन आयात कम होगा और पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। सरकार जल्द ही CAFE नियमों में संशोधन पर विचार कर रही है। यह कदम ऑटो सेक्टर को नई दिशा देगा।

Piramal Finance Secures $400 Million ECB from Global & Local Lenders

Funds from Deutsche Bank, SMBC & Others to Strengthen Balance Sheet; Capital to Fuel Growth in Retail & MSME Lending

Mumbai: Piramal Finance Ltd, the flagship NBFC of the Piramal Group, has successfully raised $400 million (approximately ₹3,350 crore) through External Commercial Borrowings (ECB) from a syndicate of global and domestic lenders. The deal includes participation from Deutsche Bank AG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), and other leading financial institutions, marking one of the largest ECB transactions in the Indian NBFC space in recent months.

The funds, raised at competitive rates, will be utilised to strengthen the company's balance sheet, refinance high-cost debt, and support expansion in high-growth retail and MSME lending segments. Piramal Finance, with a loan book exceeding ₹75,000 crore, has been focusing on secured retail credit, affordable housing finance, and small business loans following its strategic pivot away from wholesale lending.

This ECB raise reflects strong investor confidence in Piramal Finance's resilient business model and growth prospects, said a company spokesperson. The transaction comes at a time when NBFCs are actively tapping global markets for lower-cost funding amid elevated domestic borrowing rates and RBI's tight liquidity stance.

The ECB carries a 3–5-year maturity and is expected to reduce Piramal's overall cost of funds while improving net interest margins. Analysts estimate the refinancing could save ₹100–150 crore annually in interest expenses, supporting profitability in a competitive lending environment.

With India's retail credit demand growing at 15–18% annually, the fresh capital positions the company to accelerate disbursements and capture market share in underserved segments.

As NBFCs continue to play a critical role in India's financial inclusion journey, Piramal's successful ECB raise highlights the growing attractiveness of Indian credit platforms for global lenders seeking exposure to high-growth emerging markets.

.

Sh. Pradeep Karambelkar
Founder & Editor

Dr. Irshad Ahmad Khan
Sub-Editor

Sh. Pushpendra Singh
Marketing Officer

Sector Rotation in 2026: Why Defence, Infra and Manufacturing Are Gaining Attention

The Indian stock market is witnessing a noticeable shift in investment trends in 2026. Investors are gradually moving their focus from traditional high-growth sectors toward defence, infrastructure, and manufacturing. This change, known as sector rotation, usually happens when economic conditions, government policies, and global trends favour new industries. In the current scenario, these three sectors are emerging as strong pillars of India's long-term growth story.

Sector rotation is a natural part of market cycles. When certain sectors become overvalued or growth slows down, investors look for new opportunities in sectors that show strong future potential. Over the past few years, technology and consumption sectors delivered impressive returns. However, the focus is now shifting toward sectors supported by government spending, global supply chain changes, and rising domestic demand.

The defence sector is gaining significant attention due to India's strong push toward self-reliance in defence production. The government has increased defence capital expenditure and is promoting domestic manufacturing under the "Atmanirbhar Bharat" initiative. India is aiming to reduce dependence on imports and become a major defence exporter. Domestic companies involved in defence equipment, aerospace technology, and shipbuilding are receiving large orders and government support. Over the last few years, several defence companies have reported strong revenue growth and improving profitability, attracting long-term investors.

Infrastructure is another sector witnessing renewed interest. The government continues to invest heavily in roads, railways, airports, ports, and urban development projects. Large infrastructure spending not only improves connectivity and logistics but also generates employment and supports economic expansion. Infrastructure growth creates demand for multiple industries such as cement, steel, construction equipment, and engineering services. With India focusing on modernising its transport network and expanding industrial corridors, infrastructure companies are expected to see strong order inflows and revenue visibility in the coming years.

Manufacturing is also emerging as a major growth engine. Global companies are increasingly adopting the China+1 strategy, which means diversifying manufacturing bases beyond China. India is becoming a preferred destination due to its large workforce, improving infrastructure, and supportive government policies. The Production Linked Incentive (PLI) scheme has attracted investments in sectors like electronics, mobile manufacturing, automotive components, and renewable energy equipment. As manufacturing expands, it strengthens exports, creates employment, and boosts corporate earnings.

Another factor supporting these sectors is the global shift toward supply chain security. Countries are focusing on building local manufacturing capabilities to reduce dependency on imports during global disruptions. India's policy environment is aligning with this trend, which is encouraging domestic and foreign investments.

Financial markets are reflecting this sectoral shift. Stocks related to capital goods, engineering, defence production, and infrastructure development have shown strong performance and investor interest. Banks and financial institutions are also benefiting as infrastructure and manufacturing projects increase demand for loans and project financing.

However, investors should remain cautious. Sector rotation does not mean every company within a sector will perform well. Careful selection of fundamentally strong companies with healthy balance sheets and consistent order flow remains important. Market valuations and economic conditions should also be considered before making investment decisions.

In conclusion, sector rotation in 2026 highlights India's transition toward industrial expansion and infrastructure-driven growth. Defence, infrastructure, and manufacturing sectors are gaining attention due to policy support, global supply chain shifts, and strong domestic demand. These sectors are likely to play a crucial role in shaping India's economic and stock market growth in the coming years, offering promising opportunities for long-term investors.

Dr. Irshad Ahmod Khan
Sub-Editor

टाटा केमिकल्स तमिलनाडु में 515 करोड़ रुपये का नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी

सोडियम बाइकार्बोनेट और स्पेशियलिटी केमिकल्स पर फोकस, 2027 तक उत्पादन शुरू; स्थानीय रोजगार और निर्यात में वृद्धि की उम्मीद

नई दिल्ली: टाटा केमिकल्स लिमिटेड ने तमिलनाडु में 515 करोड़ रुपये का नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की घोषणा की है। यह प्लांट मुख्य रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट (बेकिंग सोडा), स्पेशियलिटी केमिकल्स और अन्य वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स का उत्पादन करेगा। कंपनी ने तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता किया है और यह यूनिट 2027 तक उत्पादन शुरू कर देगी।

टाटा केमिकल्स के एमडी रमेश वंगाल ने कहा, यह निवेश दक्षिण भारत में हमारी उपस्थिति को मजबूत करेगा और बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा। प्लांट से सालाना 1 लाख टन से अधिक सोडियम बाइकार्बोनेट का उत्पादन होगा, जो फूड, फार्मा, पर्सनल केयर और औद्योगिक उपयोग में आता है। कंपनी ने तमिलनाडु के औद्योगिक कॉरिडोर में भूमि हासिल की है, जहां बुनियादी ढांचा और बंदरगाह सुविधाएं उपलब्ध हैं।

यह यूनिट स्थानीय स्तर पर 500 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगी और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को लाभ पहुंचाएगी। टाटा केमिकल्स का लक्ष्य निर्यात बढ़ाना भी है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट की वैश्विक मांग तेजी से बढ़ रही है। कंपनी पहले से ही गुजरात और उत्तर प्रदेश में बड़े प्लांट्स चला रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेश भारत के केमिकल सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। तमिलनाडु सरकार ने कंपनी को सब्सिडी और टैक्स छूट देने का आश्वासन दिया है। यह कदम 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन से जुड़ा है। यह निवेश राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा और राष्ट्रीय स्तर पर केमिकल उत्पादन में योगदान देगा।

TATA
TATA CHEMICALS LIMITED

Britannia Bets on Quick Commerce & E-commerce to Fuel Next Phase of Growth

FMCG Major Accelerates Digital Push with Faster Delivery and Online-First Products; Targets Double-Digit Growth in 2026 Amid Shifting Consumer Habits

Mumbai: Britannia Industries, one of India's leading FMCG players, is doubling down on quick commerce and e-commerce channels to drive its next wave of growth. The company has identified these digital-first platforms as key engines to reach younger consumers, penetrate deeper into urban and semi-urban markets, and maintain momentum in a highly competitive biscuits and bakery segment.

Speaking at an investor call, Britannia's Managing Director Varun Berry said the company is witnessing strong traction on platforms like Blinkit, Zepto, Swiggy Instamart, and BigBasket. Quick commerce has become a significant growth driver for us, especially for impulse and on-the-go packs. We are also seeing robust demand on traditional e-commerce for family packs and premium ranges, Berry noted. The company has tailored smaller SKUs and exclusive online assortments to suit the fast-delivery model.

Britannia's digital sales have grown over 60% year-on-year in recent quarters, with quick commerce now contributing a meaningful portion of overall revenue. The company has partnered with multiple quick-commerce players to ensure wider availability of popular brands such as Good Day, Marie Gold, NutriChoice, and its premium offerings like the new plant-based and health-focused lines.

Industry experts view Britannia's digital pivot as timely. With quick commerce expected to reach $5–6 billion by 2027 and e-commerce continuing to grow in the food & beverage category, the strategy positions Britannia to capture the shift in consumer buying behavior toward instant gratification and online discovery.

The company has maintained steady volume growth despite input cost pressures and has focused on premiumisation and innovation to protect margins. Britannia expects overall revenue growth to remain in the double digits in 2026, with digital channels playing a disproportionately larger role.

As India's FMCG market evolves, Britannia's strong bet on quick commerce and e-commerce signals its readiness to lead in the digital-first era of consumption.

Reliance Consumer Products Adds Tamil Nadu's Manna to Its Health-Food Platter

Acquisition Strengthens Presence in South Indian Traditional Snacks and Health Segments; Aligns with Premiumisation and Regional Expansion Strategy

Mumbai: Reliance Consumer Products Limited (RCPL), the FMCG arm of Reliance Industries, has acquired Manna Foods, a popular Tamil Nadu-based brand known for its traditional health-focused snacks and ready-to-eat products. The deal, whose financial terms were not disclosed, marks RCPL's latest step in building a diversified and regionally rooted portfolio in the fast-growing health and wellness food category.

Manna Foods, founded in Coimbatore, is widely recognised in South India for its millet-based snacks, traditional sweets, and health-oriented offerings like ragi cookies, multigrain biscuits, and low-sugar savouries. The brand has built a loyal customer base among health-conscious families and urban consumers seeking authentic, nutritious alternatives to conventional packaged foods.

This acquisition strengthens our footprint in South India and complements our growing health and wellness portfolio," said a Reliance Industries spokesperson. "Manna's strong regional equity, quality focus, and innovation in millet and traditional ingredients align perfectly with our strategy to offer premium, health-oriented products to Indian consumers."

RCPL has been rapidly expanding its food and beverage business through a combination of in-house brands and strategic acquisitions. The addition of Manna follows earlier moves into premium snacks, beverages, and confectionery, positioning RCPL to compete more effectively against established players like Britannia, ITC, and Parle in the health-food segment.

Industry experts view the deal as a smart play to tap into the rising demand for regional, millet-based, and low-glycemic products, especially among younger urban consumers and in tier-2 and tier-3 cities. Millet consumption has gained significant traction in India following government promotion of millets as a superfood.

With India's packaged food market projected to grow at 12–15% annually, RCPL's aggressive inorganic and organic expansion is expected to help it capture a larger share of the organised segment. The acquisition also strengthens Reliance Retail's private-label and quick-commerce offerings through JioMart and other channels.

Adani Energy Secures Japanese Funding for Green Energy Corridor Project

Multi-Billion Yen Loan from JBIC and Mizuho to Accelerate 2 GW Transmission Line; Boosts India's Renewable Evacuation Capacity and Regional Grid Connectivity

Ahmedabad: Adani Energy Solutions Limited (AESL), the power transmission and distribution arm of the Adani Group, has secured significant funding from Japanese financial institutions to develop a major green energy corridor in India. The financing, led by the Japan Bank for International Cooperation (JBIC) and Mizuho Bank, totals several billion yen and will support the construction of a high-voltage transmission line designed to evacuate renewable power from western India to high-demand regions.

The project, part of AESL's broader Green Corridor initiative, involves building a 2 GW-capacity corridor linking renewable-rich zones in Gujarat and Rajasthan to load centres in northern and central India. Once complete, it will help integrate large-scale solar and wind generation into the national grid, reducing curtailment and supporting India's target of 500 GW non-fossil capacity by 2030.

This funding from Japan underscores the global confidence in India's renewable energy transition and our commitment to building sustainable infrastructure, said an AESL spokesperson. The corridor will feature state-of-the-art green technologies, including high-efficiency transmission lines and smart grid elements to minimise losses and enhance reliability.

The Japanese financing aligns with Japan's commitment to support clean energy projects in partner countries under its Asia Energy Transition Initiative. JBIC and Mizuho have been active in India's renewable sector, backing multiple solar and wind projects in recent years.

Analysts view the deal positively, noting that it strengthens AESL's funding diversification and reduces reliance on domestic borrowing amid elevated interest rates. The corridor is expected to be operational by 2028 and will create thousands of jobs during construction and operation.

As India accelerates its clean energy journey, such international partnerships are critical to building the transmission backbone needed for large-scale renewable integration and achieving net-zero goals by 2070.

Steel Exports: India Eyes New Growth in Middle Eastern and Asian Markets

Shift from Traditional Markets as Domestic Demand Rises and Global Trade Dynamics Change; Targets 20% Export Growth in FY26

Mumbai: : India is actively working to diversify its steel exports by focusing on high-growth markets in the Middle East and Asia, moving away from over-reliance on traditional destinations like Europe and the US. The Ministry of Steel and industry bodies have identified the Middle East (UAE, Saudi Arabia, Qatar) and Southeast Asia (Vietnam, Indonesia, Thailand) as priority regions to offset challenges in Western markets, where protectionist measures and subdued demand have slowed shipments.

In FY25, India exported around 7.5 million tonnes of steel, with Europe and North America accounting for nearly 40% of the total. However, rising anti-dumping duties in the EU, US tariffs, and weaker industrial activity have prompted exporters to look eastward. The Middle East, with its massive infrastructure projects under Vision 2030 and similar initiatives, offers strong demand for construction-grade steel, pipes, and rebar. Southeast Asia's booming manufacturing and urbanisation further add to the opportunity.

Steel industry leaders say the shift is already underway. Major players like JSW Steel, Tata Steel, and JSPL have ramped up shipments to the UAE and Vietnam, where India enjoys competitive advantages in price and logistics. The government is also facilitating trade through bilateral talks and participation in regional forums.

Experts estimate that redirecting exports could help achieve

20% growth in steel exports in FY26, pushing total volumes toward 9 million tonnes. The strategy also reduces vulnerability to global trade disruptions and supports India's target of 300 million tonnes of steel production capacity by 2030.

With domestic steel demand growing steadily due to infrastructure and housing projects, the diversification move ensures that excess capacity finds remunerative markets abroad, sustaining industry profitability and employment in the sector.

Zydus Lifesciences Cleared to Sell Generic Cancer Drug; SC Directs Bristol Myers to Disclose Patent Map

Landmark Order Ends Prolonged Patent Battle; Affordable Lenalidomide Access for Thousands of Patients, Boost to India's Generic Oncology Push

New Delhi: In a major relief for cancer patients, the Supreme Court has cleared the way for Zydus Lifesciences to launch its generic version of lenalidomide, a critical drug used to treat multiple myeloma and certain lymphomas. The apex court, while disposing of the long-running patent dispute, directed originator Bristol Myers Squibb (BMS) to file a comprehensive map of its patents related to lenalidomide within four weeks, ensuring greater transparency in future patent challenges.

The order ends years of litigation between Zydus and BMS over the validity and scope of secondary patents on Revlimid (lenalidomide). Zydus had argued that the drug's core patent

had expired and that BMS's secondary claims were not innovative enough to block generics. The Supreme Court's directive to BMS to disclose its full patent portfolio is seen as a significant step toward preventing 'evergreening' tactics that delay affordable medicines.

Zydus is expected to launch its generic lenalidomide in various strengths shortly, offering it at 60-70% lower prices than the branded version. The drug is a lifeline for thousands of multiple myeloma patients in India, where treatment costs have been a major barrier.

This is a victory for patients and public health. Affordable access to life-saving drugs must take precedence, said a senior lawyer representing Zydus. The company already has a strong oncology portfolio in the US and India, and the lenalidomide launch will strengthen its position in the growing generic cancer drug market.

Industry experts hailed the judgment as a precedent that could accelerate generic entry for other high-value drugs. As India continues to lead global generic supply, the decision reinforces the balance between innovation and affordability in life-saving medicines.

जल्द ही पड़ोसी से सीधे बिजली खरीद-बेच सकेंगे: नया नियम तैयार

पीयर-टू-पीयर एनर्जी ट्रेडिंग से बिजली बिल में कमी, रिन्यूएबल ऊर्जा को बढ़ावा; 2026 से पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने की उम्मीद

नई दिल्ली: भारत में जल्द ही आम लोग अपने पड़ोसी से सीधे बिजली खरीद या बेच सकेंगे। केंद्र सरकार ने 'पीयर-टू-पीयर' (P2P) एनर्जी ट्रेडिंग के लिए नियमों को अंतिम रूप दे दिया है, जिससे रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले लोग अतिरिक्त बिजली अपने आस-पास के लोगों को बेच सकेंगे। यह व्यवस्था 2026 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो सकती है।

वर्तमान में रूफटॉप सोलर से बची बिजली ग्रिड में जाती है और उसके बदले क्रेडिट मिलता है। नए नियमों के तहत लोग बिजली को सीधे पड़ोसी, दोस्त या किसी अन्य उपभोक्ता को बेच सकेंगे। इससे बिजली की कीमतें बाजार के अनुसार तय होंगी और बिजली बिल में 20-40% तक की बचत हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सोलर अपनाने को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, यह कदम भारत को रिन्यूएबल एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाने और ग्रिड पर दबाव कम करने में मदद करेगा। सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और ब्लॉकचेन-बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम तैयार करने पर काम शुरू कर दिया है, ताकि ट्रांजेक्शन पारदर्शी और सुरक्षित रहे।

यह व्यवस्था रूफटॉप सोलर की क्षमता 30 GW तक पहुंचाने के लक्ष्य को गति देगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक लाखों घरों में यह सुविधा उपलब्ध हो सकती है। इससे न केवल बिजली की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। यह भारत की ऊर्जा क्रांति का एक नया अध्याय होगा।

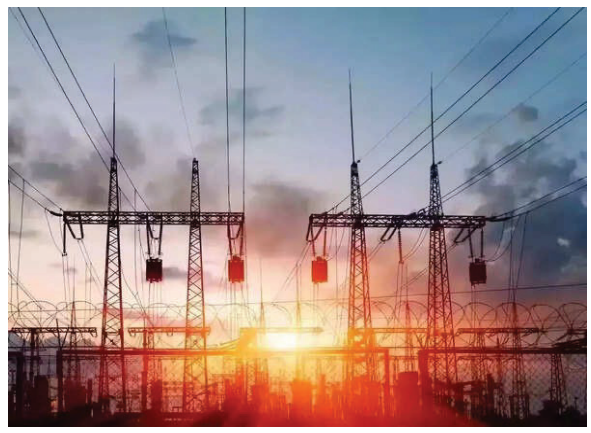

भारत ने रिफाइनर्स से कहा: अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदें, व्यापार समझौतों में बदलाव के बीच

रूस से आयात में कमी की भरपाई, अमेरिकी तेल पर कम टैरिफ और वेनेजुएला पर प्रतिबंधों में ढील से नया अवसर; ऊर्जा सुरक्षा और लागत बचत पर जोर

नई दिल्ली: भारत सरकार ने देश के प्रमुख तेल रिफाइनर्स से अमेरिका और वेनेजुएला से अधिक कच्चे तेल की खरीद पर विचार करने को कहा है। यह निर्देश ऐसे समय आया है जब भारत-US व्यापार समझौते की चर्चाएं तेज हैं और वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों में कुछ ढील की संभावना बढ़ी है। वाणिज्य एवं पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि रूस से तेल आयात में हालिया कमी की भरपाई के लिए ये विकल्प तलाशे जा रहे हैं।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और इसकी 85% जरूरत आयात से पूरी होती है। पिछले कुछ महीनों में रूसी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है। अब अमेरिकी तेल पर भारत को कम टैरिफ मिलने की उम्मीद है, जिससे लागत में बचत होगी। वेनेजुएला से सस्ता और भारी क्रूड तेल मिल सकता है, जो भारतीय रिफाइनरियों के लिए उपयुक्त है।

IOC, BPCL और HPCL जैसे रिफाइनर्स ने पहले ही अमेरिकी क्रूड की खरीद बढ़ाई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2026 में अमेरिका और वेनेजुएला से आयात 15-20% तक बढ़ सकता है। यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और रूस पर निर्भरता को कम करेगा।

विश्लेषकों का कहना है कि व्यापार समझौते से तेल आयात में विविधता आएगी, जिससे वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर कम होगा। भारत 2030 तक ऊर्जा आयात में 10% कमी का लक्ष्य रखता है। यह रणनीति उस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी। रिलायंस और अन्य निजी रिफाइनर्स भी इस दिशा में सक्रिय हैं।

MPBIL/2013/49052
INVESTMENT AVENUES®
(इन्वेस्टमेंट एवेनयुस)
(A Publication of Vision Invest Tech Pvt. Ltd.)

INVESTMENT AVENUES
CALL FOR ARTICLES
Share Your Knowledge with
INVESTMENT AVENUES
We invite individual, professionals, and entrepreneurs to contribute their expertise and experiences.

- STOCK MARKET
- MUTUAL FUNDS
- REAL ESTATE
- STARTUPS & ENTREPRENEURSHIP

Guidelines:
1. Article must be original
2. Submit in MS Word format
3. Length should not exceed 500 words

editor@investmentavenues.in
write with us, inspire others, and make your voice heard in the world of investments!

INVESTMENT AVENUES®
Looking To Invest In Real Properties & Valued Businesses In BhopaL
Discover genuine real estate and well-assessed business opportunities — safe-to-invest and growth-oriented.
Secure Deals. Smart Investments.
EMAIL: INVESTMENTAVENUES90@GMAIL.COM
CONTACT: +91 73899 26586

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj
Technical Head
anil.stockcare@gmail.com

AII level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

• As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
• If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1
• If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
• Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
• If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
• If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock Name	closing	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	25471	26400	26204	25838	25642	25276	25080	24714
BANK NIFTY	60187	61426	61151	60669	60394	59912	59637	59155
SENSEX	82627	85835	85161	83894	83220	81953	81279	80012
FINNIFTY	28126	28614	28469	28298	28153	27982	27837	27666
MIDCAP	13628	14272	14125	13876	13729	13480	13333	13084
ACC	1640	1773	1743	1692	1662	1611	1581	1530
AXISBANK	1331	1399	1380	1355	1336	1311	1292	1267
ABCAPITAL	335	370	363	349	342	328	321	307
BHARTIARTL	1999	2102	2080	2039	2017	1976	1954	1913
BHEL	255	292	284	270	262	248	240	226
BEL	378	412	401	389	378	366	355	343
BIOCON	435	461	454	444	437	427	420	410
CDSL	1336	1481	1447	1391	1357	1301	1267	1211
DATAPATTERN	2755	3115	3021	2888	2794	2661	2567	2434
ESCORTS	3580	4067	3969	3775	3677	3483	3385	3191
EICHERMOTOR	8067	9484	8800	8433	7749	7382	6698	6331
FEDERAL BANK	288	309	301	295	287	281	273	267
GRINFRAPOJECT	975	1105	1071	1023	989	941	907	859
HDFCBANK	904	982	966	935	919	888	872	841
HCLTECH	1458	1809	1715	1586	1492	1363	1269	1140
HINDUNILVR	2301	2601	2540	2421	2360	2241	2180	2061
HAL	4204	4554	4408	4306	4160	4058	3912	3810
HYUNDAI	2180	2263	2232	2206	2175	2149	2118	2092
IOC	177	188	185	181	178	174	171	167
ICICIBANK	1415	1480	1456	1436	1412	1392	1368	1348
INFY	1369	1749	1638	1504	1393	1259	1148	1014
ITC	314	340	335	324	319	308	303	292
KOTAKBNK	422	446	441	431	426	416	411	401
LICHOUSING	507	540	534	520	514	500	494	480
LT	4172	4364	4281	4227	4144	4090	4007	3953
LUPIN	2194	2306	2270	2232	2196	2158	2122	2084
MARUTI	15211	16032	15746	15478	15192	14924	14638	14370
M&M	3533	3967	3877	3705	3615	3443	3353	3181
MGL	1107	1275	1238	1173	1136	1071	1034	969
MAZGAONDOC	2344	2628	2570	2457	2399	2286	2228	2115
PFC	400	451	441	420	410	389	379	358
RECLTD	346	407	393	369	355	331	317	293
RELIANCE	1419	1513	1493	1456	1436	1399	1379	1342
SBIN	1196	1337	1271	1233	1167	1129	1063	1025
SUNPHARMA	1699	1739	1730	1714	1705	1689	1680	1664
SHRIRAMFINANCE	1064	1184	1135	1100	1051	1016	967	932
TITAN	4175	4540	4459	4317	4236	4094	4013	3871
TCS	2695	3370	3191	2943	2764	2516	2337	2089
TATAMOTORS	379	404	396	387	379	370	362	353
UPL	723	782	770	746	734	710	698	674
VALIENT	266	307	295	281	269	255	243	229
WIPRO	214	252	243	228	219	204	195	180

अडानी की अगुवाई वाली अंबुजा सीमेंट और संघी इंडस्ट्रीज का विलय एनसीएलटी से मंजूर

5,000 करोड़ रुपये से अधिक का सौदा, अंबुजा की क्षमता 100 मिलियन टन पार; सीमेंट बाजार में मजबूत स्थिति, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी

अहमदाबाद: राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) ने अडानी समूह की अगुवाई वाली अंबुजा सीमेंट्स और संघी इंडस्ट्रीज के विलय को मंजूरी दे दी है। यह सौदा करीब 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का है और इससे अंबुजा की कुल सीमेंट उत्पादन क्षमता 100 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) के पार पहुंच जाएगी। एनसीएलटी की अहमदाबाद बेंच ने मंगलवार को यह आदेश पारित किया, जिसके बाद अ केवल अंतिम मंजूरी और नियामक औपचारिकताएं बाकी हैं।

अंबुजा सीमेंट्स ने 2022 में संघी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण किया था। संघी की गुजरात में 6.1 MTPA क्षमता वाली रिफाइनरी और अन्य संपत्तियां अंबुजा को पश्चिम भारत में मजबूत स्थिति देंगी। विलय से कंपनी की बाजार हिस्सेदारी बढ़ेगी और परिवहन लागत में कमी आएगी। अंबुजा के सीईओ अजय कपूर ने कहा, "यह विलय हमारी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे हमारा प्रोडक्शन नेटवर्क और मजबूत होगा और ग्राहकों को बेहतर कीमतों पर सीमेंट मिलेगा।"

सीमेंट उद्योग में यह विलय अडानी समूह की तेजी से बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है। अंबुजा अब अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सीमेंट कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन लंबे समय में दक्षता और सप्लाई चेन में सुधार होगा।

विलय के बाद अंबुजा की क्षमता 100 MTPA से अधिक हो जाएगी। कंपनी ने हाल के वर्षों में कई अधिग्रहण किए हैं, जिसमें सांगही के अलावा पेन्ना और ओडिशा के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। यह कदम भारत के इंफ्रा विकास और आवास मांग को समर्थन देगा। यह विलय सीमेंट सेक्टर में एकीकरण का नया दौर शुरू करेगा।

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.

प्रकाशक एवं मुद्रक: प्रदीप कारबेलकर, सी-101, नेहरू नगर स्वत्वाधिकार द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रा.लि., इ-4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462016, से प्रकाशित एवं DigitalLok, सागर हाई स्ट्रीट, अयोध्या बायपास रोड, डी मार्ट के पास, भोपाल, (म.प्र.) - 462010। संपादक: प्रदीप कारबेलकर (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)। फोन: +9198262 23075 वेबसाइट: www.investmentavenues.in